PK टाइम्स

दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 338 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | मंगलवार 23 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

लखनऊ की कोचिंग में आग,
15 स्टूडेंट्स की मौत

बचने के लिए बाथरूम में छिपे, दम घुटने से जान गई; एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका

लोक टुडे

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं।

जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह अलीगंज इलाके में है। बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3ष्ठ आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है।

जानकारी के मुताबिक, आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। जयंत नाम के एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूद कर जान बचाई। लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।

अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे ष्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर हैं। SDRF और NDRF भी पहुंची है। फायरकर्मियों ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़ा है, जिससे शव निकाले जा रहे हैं। घटनास्थल पर मृतकों और घायलों के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गईं। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मंजर को देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा- मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी हैं।

मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर बोलीं- अटॉप्सी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा,अलीगंज में आग की घटना घटी है। जितने को हम बचा सकते हैं, हम उनको बचाएंगे। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। अभी सब शुरू हो गया है।

राहुल गांधी बोले- हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। राहुल गांधी ने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।

अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जताया, बोले- हादसे दोबारा न हों, सभी को मिलकर प्रयास करना होगा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने सरकार से घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसों का शिकार किसी भी परिवार के बच्चे हो सकते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को मिलकर गंभीर प्रयास करने चाहिए।

नवीन मंडियों और फूड पार्कों के लिए
सरकार देगी 25% दर पर जमीन

बजट 2026-27 की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू

मंडियों की भूमि लगभग नि:शुल्क प्राप्त हो सकेगी

'लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025' के तहत निवेशकों और विकासकर्ताओं को मिलेगी 75 फीसदी की भारी छूट

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों, व्यापार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राज्य की भजनलाल सरकार ने सोमवार को एक नीतिगत फैसला लिया है। प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को गति देने और नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस नए आदेश के तहत बजट वर्ष 2026-27 में घोषित नवीन मंडियों, गौण मंडियों और फूड पार्कों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया गया है। व्यापार जगत को अब तक की सबसे बड़ी राहत देते हुए भूमि की कीमतों में भारी कटौती की है। अब इन विशिष्ट व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए विकास प्राधिकरणों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तय आरक्षित दर या डीएलसी दर की महज 25 प्रतिशत कीमत पर ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस कदम से निवेशकों को सीधे तौर पर 75 फीसदी की बड़ी वित्तीय छूट का लाभ मिलेगा, जिससे परियोजनाओं की शुरुआती लागत बेहद कम हो जाएगी।

'लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025' के तहत विशेष रियायत-

विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, भूमि का यह रियायती आवंटन राज्य की प्रतिष्ठित 'भूमि आवंटन नीति-2025' के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। विभाग ने हाल ही में 18 जून को इस नीति में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी स्पष्टीकरण भी जोड़े थे, जिसके बाद सोमवार को मंडियों और फूड पार्कों के लिए इस विशेष रियायत पर अंतिम मोहर लगा दी गई। इस नीतिगत निर्णय का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट और जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण अटकने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देना है।

किसानों की बदलेगी तकदीर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा 'बूस्ट' -

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को पेश किए गए राज्य बजट के इस फैसले से राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में नई गौण मंडियां खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। इससे उनका परिवहन खर्च बचेगा। आरक्षित दर के मात्र 25 फीसदी पर जमीन मिलने से फूड पार्कों में निजी डेवलपर्स बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स (जैसे कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और पल्पिंग प्लांट) स्थापित कर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर ही फल, सब्जियों और अनाज की प्रोसेसिंग होने से कृषि उत्पादों की कटाई के बाद होने वाली बर्बादी रुकेगी और किसानों को उनकी फसल का दोगुना तक दाम मिल सकेगा।

निर्माण से लेकर लॉजिस्टिक्स तक चमकेगा बाजार

इस बड़े नीतिगत फैसले से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। आधुनिक मंडियों और एग्रो-फूड पार्कों के निर्माण चरण से ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद परिवहन पैकेजिंग, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, रिटेल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

निकायों को तुरंत भूमि चिन्हित करने के निर्देश

शासन सचिवालय से आदेश जारी होते ही नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि बजट घोषणाओं के अनुरूप संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त सरकारी या निकाय की भूमि को तुरंत चिन्हित किया जाए, ताकि आवंटन की प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक देरी के समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

बजट घोषणाएं धरातल पर -

राज्य सरकार अपनी बजटीय घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर लाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। अभी जारी हुआ यह सर्कुलर इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

आर्थिक तरक्की और रोजगार के खुलेंगे नए द्वार -

सरकार के इस एकल फैसले से न केवल कृषि अवसंरचना मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियों को भारी गति मिलेगी। नए फूडपार्क और मण्डियों के संचालन से स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो राजस्थान की जीडीपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

किसानों और स्थानीय व्यापार को बड़ा बूस्ट -

सरकार का मानना है कि इस नीतिगत सरलीकरण से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नई मण्डियों का विकास तेजी से होगा। इसमें नई गौण मण्डियों के खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिलों में फूडपार्क स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। व्यापारिक संगठनों और मंडी समितियों को जमीन के लिए भारी भरकम राशि नहीं चुकानी होगी, जिससे प्रोजेक्ट की लागत में कमी आएगी।

उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल

मुंबई

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदनवन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया।

इस दौरान शिंदे ने कहा- जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष-बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब 40 विधायक थे और अब छक्के लग चुके हैं। हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसीलिए आज ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए।

उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने ङ्क पर लिखा- पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। कम से कम यह मान लीजिए कि लालच की वजह से आपने रातोंरात बिना किसी शर्म के यह सब छोड़ दिया। 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। वहीं उद्धव गुट में 9 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। 2022 के बाद शिवसेना में दूसरी बार टूट हुई।

यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है

नई दिल्ली

भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में नई बातचीत शुरू हुई है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच शुरुआती चर्चा चल रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है।

क्या आरएसएस की भारत की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए?

नीरज कुमार दुबे

असल में कांग्रेस की समस्या संघ के पंजीकरण से नहीं, संघ के प्रभाव से है। जिस संगठन ने बिना सरकारी धन, बिना विदेशी सहायता और बिना सत्ता के सहारे सौ वर्षों तक राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उससे कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने एक बार फिर वही पुराना शोर उठाया है कि संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का पत्र और उसके बाद खड़ा किया गया राजनीतिक कोलाहल इस बात का प्रमाण है कि संघ विरोधियों के पास न तथ्य बचे हैं, न तर्क। वह केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस संगठन को जनता का भरोसा और समाज का समर्थन हासिल हो, उसे बदनाम करने का सबसे आसान तरीका संदेह फैलाना होता है।

लेकिन इस बार संघ ने भी स्पष्ट और सीधा उत्तर दिया है। मोहन भागवत ने साफ कहा, ह्लहिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है ह्व यह उस पूरी मानसिकता पर प्रहार है जो मानती है कि भारत की हर सांस्कृतिक चेतना को सरकारी मुहर से ही वैधता मिलेगी। भागवत ने कहा कि संघ 1925 में स्थापित हुआ था। क्या तब अंग्रेजों से जाकर पंजीकरण कराया जाता? साथ ही स्वतंत्रता के बाद भी भारत के संविधान ने कभी यह अनिवार्य नहीं किया कि हर स्वैच्छिक संगठन सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो तभी वह अस्तित्व में रह सकता है।

असल में कांग्रेस की समस्या संघ के पंजीकरण से नहीं, संघ के प्रभाव से है। जिस संगठन ने बिना सरकारी धन, बिना विदेशी सहायता और बिना सत्ता के सहारे सौ वर्षों तक राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उससे कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है। संघ ने चरित्र निर्माण किया, अनुशासन दिया, समाज को जोड़ा, सेवा का संस्कार दिया और राष्ट्रवाद को जीवन का व्यवहार बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस का एक हिस्सा वर्षों तक विदेशी शक्तियों के सामने वैचारिक समर्पण करता रहा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करने वाली राजनीति आज संघ से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांग रही है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान कहीं नहीं कहता कि हर सामाजिक संगठन को पहले सरकार के सामने सिर झुकाकर अनुमति लेनी होगी। सोसाइटी कानून, न्यास कानून और अन्य व्यवस्थाएं केवल कानूनी सुविधाओं के लिए हैं, अस्तित्व के लिए नहीं।

संघ के पंजीकरण प्रमाणपत्र को देखने की चाह रखने वाले प्रियांक खरगे, पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में मंत्री होना कानून से ऊपर होना नहीं होता। किसी मंत्री की व्यक्तिगत इच्छा कानून नहीं बन जाती। यदि कानून में अनिवार्यता नहीं है, तो केवल राजनीतिक नफरत के कारण किसी संगठन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। यही विधि का शासन है, यही संविधान की आत्मा है।

संघ को समझने के लिए उसकी मूल प्रकृति को समझना आवश्यक है। संघ कोई पारंपरिक कार्यालयी संस्था नहीं, बल्कि समाज आधारित आंदोलन है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसे सदस्यता कार्ड, शुल्क और कागजी ढांचे की बजाय शाखा, संस्कार और स्वयंसेवा के आधार पर खड़ा किया। आज भी कोई व्यक्ति शाखा में जाकर स्वयंसेवक बन सकता है। यही कारण है कि संघ समाज के बीच रहता है, किसी फाइल में बंद नहीं रहता। संघ अपने आरम्भकाल से ही सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता रहा है। संघ में औपचारिक सदस्यता और कठोर संस्थागत नियंत्रण नहीं होता। शाखाएं अपने संसाधनों से चलती हैं और संगठन का संचालन सामाजिक सहभागिता से होता है।

इतिहास यह भी बताता है कि संघ को बार-बार राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया, आपातकाल में हजारों स्वयंसेवक जेल भेजे गए, बाबरी प्रकरण के बाद भी हमला हुआ। लेकिन हर बार संघ और अधिक मजबूत होकर निकला। इसका कारण यह था कि संघ की जड़ें सत्ता में नहीं, समाज में हैं। मोहन भागवत ने भी याद दिलाया कि सरकारें संघ पर प्रतिबंध लगाती रहीं, इसका अर्थ ही यह है कि सरकारें संघ के अस्तित्व और प्रभाव को मानती रही हैं।

देखा जाये तो संघ विरोधी बार बार पारदर्शिता और कराधान का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन वह जानबूझकर न्यायालयों के निर्णयों को नजरअंदाज करते हैं। ह्लगुरु दक्षिणाह्व को लेकर न्यायालयों ने पारस्परिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट माना कि स्वयंसेवकों का स्वैच्छिक योगदान करयोग्य आय नहीं माना जा सकता। संघ ने कभी कानून से छूट नहीं मांगी। उसने केवल वही स्वीकार किया जो कानून कहता है। कानून जहां लागू होता है, वहां संघ के सहयोगी संगठन विधिवत पंजीकृत हैं, लेखा परीक्षण कराते हैं और अपने प्रतिवेदन भी प्रकाशित करते हैं।

यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस का पाखंड खुलकर सामने आता है। दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी आज संघ से पारदर्शिता मांग रही है, जबकि स्वयं उसके इतिहास पर आपातकाल, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विदेशी प्रभाव के आरोप लगे हुए हैं। जो दल लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल थोप सकता है, वह आज लोकतांत्रिक मूल्यों का उपदेश दे रहा है। यह राजनीतिक हास्य से अधिक कुछ नहीं।

मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा कि संघ खुलकर काम करता है, किसी गुप्त संगठन की तरह नहीं। लाखों शाखाएं, हजारों सेवा प्रकल्प, शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा राहत, सामाजिक समरसता, वनवासी कल्याण, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, संघ का हर कार्य समाज के सामने है। यदि संघ में कुछ छिपा होता तो वह सौ वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में इतने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता।

दरअसल संघ की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसने राष्ट्रवाद को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा। जब भी देश पर संकट आया, स्वयंसेवक सबसे पहले खड़े दिखाई दिए। विभाजन के समय राहत कार्य हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, महामारी का दौर हो या सीमा पर सैनिकों के परिवारों की सहायता, संघ के कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय रहे। यही कारण है कि भारत का सामान्य नागरिक संघ को कागजी संस्था नहीं, राष्ट्रीय चेतना का प्रहरी मानता है।

संघ को लेकर सबसे अधिक भ्रम उन लोगों में है जो भारत को केवल सत्ता और चुनाव की नजर से देखते हैं। संघ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए काम करता है। यही कारण है कि वह राजनीतिक उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। मोहन भागवत ने हाल में कहा था कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला संगठन भी है। यह कथन बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने कभी शाखा देखी ही नहीं, वह संघ पर सबसे अधिक आरोप लगाते हैं।

देखा जाये तो आज आवश्यकता इस बात की है कि संघ को राजनीतिक चश्मे से नहीं, उसके कार्यों से देखा जाए। यदि कोई संगठन बिना सरकारी सहायता के, बिना विदेशी धन के और बिना सत्ता के दबाव के सौ वर्षों तक राष्ट्रसेवा करता है, तो उसकी वैधता किसी सरकारी रजिस्टर से नहीं, जनता के विश्वास से तय होती है।

कांग्रेस और संघ विरोधियों को यह समझ लेना चाहिए कि संघ को डराकर, बदनाम करके या कानूनी भ्रम फैलाकर कमजोर नहीं किया जा सकता। संघ की शक्ति कागजों से नहीं, करोड़ों स्वयंसेवकों के समर्पण से आती है। उसका अस्तित्व किसी मंत्री की कृपा पर नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर आधारित है। जो सौ वर्षों से राष्ट्र को सब कुछ दे रहा हो, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्र स्वयं उसका परिचय बन जाता है।

साथ ही संघ को किसी वंशवादी राजनीति से चरित्र प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस संगठन ने सौ वर्षों तक बिना सत्ता, बिना सरकारी संरक्षण और बिना विदेशी सहारे के राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उसकी पहचान किसी सरकारी मुहर से नहीं होती। संघ का परिचय उसके करोड़ों स्वयंसेवकों की तपस्या है, उसकी शाखाओं का अनुशासन है, उसकी सेवा का विस्तार है और भारत माता के प्रति उसका अखंड समर्पण है। राजनीतिक दल सत्ता से बनते और मिट जाते हैं, लेकिन संघ जैसी राष्ट्रशक्ति पीढ़ियों तक समाज की चेतना में जीवित रहती है। संघ को मिटाने के सपने देखने वाले आते जाते रहे, लेकिन संघ आज भी उतना ही दृढ़, उतना ही प्रभावशाली और उतना ही राष्ट्रनिष्ठ खड़ा है, क्योंकि उसका आधार सत्ता नहीं, भारत की सनातन आत्मा है।

संपादकीय

एक थोपे युद्ध का अंत

दुनिया ने राहत की सांस महसूस की होगी! आर्थिक मंदी, ऊर्जा-खाद्य संकट और तबाही की भयावहता अब नहीं डराएगी। ईरान का 47 साल लंबा वैश्विक वनवास और पाबंदियां अब समाप्त होंगी। होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से ईरान के 11 जहाज कच्चा तेल लेकर गुजरे। कतर की एलएनजी के टैंकर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के जहाज भी गुजरने लगे हैं। युद्ध से पहले जो होर्मुज था, उसका वही स्वरूप और रास्ता खुलने लगा है। अमरीका ने भी होर्मुज-ओमान खाड़ी में अपनी सैन्य नाकेबंदी हटा ली है। अमरीकी सेनाएं भी धीरे-धीरे लौट जाएंगी। यह अमरीका-ईरान के बीच समझौते के मसविदे पर हस्ताक्षर कर सहमति देने के बाद के माहौल, उल्लास, निष्कंटक आवाजाही के दृश्य हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस के ह्यवर्साय पैलेसह्न में, जी-7 सम्मेलन के दौरान ही, समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दस्तखत किए। इसी के साथ 110 दिन से जारी ईरान युद्ध समाप्त हो गया। बमबारी, मिसाइल, ड्रोन की भयानक आवाजें, विस्फोट, आग की लपटें और धुआं, अंततः विध्वंस का दौर थम गया। मानवता जिंदा रह सकेगी, फिलहाल यह तय किया गया है। अब आगे के 60 दिन वाताओं के दौर जारी रहेंगे। अंतिम समाधान और सहमति तय की जाएगी, लेकिन यह निश्चित है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब युद्ध का आदेश नहीं देंगे। इस युद्ध ने उनकी कई गलतफहमियां दूर की हैं, युद्ध के बारे में वह आत्ममंथन कर रहे होंगे, शायद क्यूबा को भी बख्श देंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हरेक देश वेनेजुएला नहीं होता। यह युद्ध-समाप्ति बेहद त्रासद रही है, क्योंकि कुल 7500 से अधिक मौतें हुईं। पेंटागन और ईरान वॉर कॉस्ट ट्रैकर के मुताबिक, दोनों देशों को करीब 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। दुनिया के वे देश, जिनका युद्ध से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, उन्हें भी करीब 112 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। खाड़ी देशों को करीब 194 अरब डॉलर का नुकसान ही झेलना नहीं पड़ा, बल्कि करीब 36 लाख नौकरियां/रोजगार खत्म हो गए। करीब 40 लाख लोग गरीबी-रेखा के नीचे जाने को विवश हुए। अमरीका-इजरायल ने ईरान पर करीब 2500 हमले किए और उसे खंडहर बना दिया। अकेले ईरान को करीब 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अमरीका को भी करीब 10.64 लाख करोड़ रुपए फूंकने पड़े। उसकी 10 लाख करोड़ रुपए की मिसाइलें और ड्रोन ईरान ने तबाह कर दिए। अमरीका के 15 सैनिक भी मारे गए और खाड़ी देशों में उसके सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया है। 'सुपर पॉवर' की छवि, बेशक, खंडित हुई है। यह माना जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस समझौते के लिए तैयार होना पड़ा, कदाचित झुकना पड़ा। उन्होंने जी-7 बैठक के दौरान यह स्वीकार कर सभी को चौंका दिया कि चार सप्ताह में रिजर्व खत्म हो जाते। दुनिया भर के रिजर्व भी खत्म हो जाते। तेल-गैस खत्म हो जाते, तो दुनिया में अराजकता फैल जाती। महत्वपूर्ण और घातक हथियारों के भंडार भी खत्म हो रहे थे। उन्हें आगामी तीन सालों में भी भरा नहीं जा सकता। आर्थिक मंदी मंडरा कर डराने लगी थी, लिहाजा युद्ध समाप्त करने के अलावा, कोई और विकल्प नहीं था।

चिंतन-मनन

कर्म से बना है वर्ण

मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना गुण और कर्मों के हिसाब से की जाती है, फिर भी तू मुझे कभी न खत्म होना वाला और कर्मों के बंधन से मुक्ति ही जान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, अब ऐसा मान लेते हैं कि जो जिस घर में जन्म लेता है, वह उसी वर्ण का कहलाता है। जबकि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर शुरू हुई थी। पहले जब बच्चे को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, तब तक वह किसी वर्ण का नहीं कहलाता था। वहां गुरु अपने शिष्यों की रुचि को जानकर उसके हिसाब से उन्हें पढ़ाते थे।

वेदों को पढ़ने में रुचि लेने वालों को ब्राह्मण, युद्ध कला में महारथी को क्षत्रिय, व्यापार में रुचि वाले को वैश्य और सेवा भाव वाले को शूद्र की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद वे समाज में उसी के हिसाब से काम करते थे। यही भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर चार वर्णों की रचना की हैं, जिससे सभी मनुष्य कर्मों में लगे रहें। ये सब करते हुए भी तुम मुझे कभी न खत्म होने वाला और कुछ न करने वाला जानो। सब कुछ करते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता।

दल-बदल की राजनीति और लोकतंत्र का भविष्य

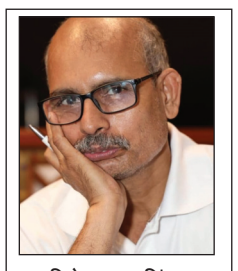

विनोद कुमार सिंह

जनादेश की चोरी या राजनीतिक अवसरवाद जनादेश बनाम दल-बदल।भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक अवसरवाद का बंधक बनता जा रहा है?

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जनता को लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी माना जाता है। संविधान की मूल भावना भी यही है कि सत्ता का स्रोत जनता है, जनता जर्नादन का जनादेश सर्वोपरि है।मतदाता किसी प्रत्याशी को केवल उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं चुनता,बल्कि उसके राजनीतिक दल,विचारधारा,नेतृत्व और चुनावी घोषणापत्र पर विश्वास व्यक्त करता है।यही कारण है कि चुनाव परिणाम केवल सीटों की गणना नहीं,बल्कि जनता की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं।दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में जिस प्रकार दल-बदल की प्रवृत्ति बढ़ी है,उसने लोकतंत्र की आत्मा जनादेश की पवित्रता और राजनीतिक नैतिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।एक ओर भाजपा व एन डी ए की केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।विकसित भारत,आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत जैसे लक्ष्य राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं।दूसरी ओर राजनीतिक दलों के भीतर बढ़ती अस्थिरता,वैचारिक प्रतिबद्धता का क्षरण और सत्ता प्राप्ति की बढ़ती होड़ लोकतंत्र को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर रही है।जनता जिन प्रतिनिधियों को किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनकर भेजती है,वे कुछ वर्षों बाद या कभी-कभी कुछ महीनों बाद ही अपना दल बदल लेते हैं।इससे सबसे अधिक आघात मतदाता के विश्वास को पहुँचता है।भारतीय राजनीति में दल-बदल की समस्या नई नहीं है।वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में कई बार पार्टी बदलने की घटना के बाद ₹आया राम,गया राम₹ भारतीय राजनीति का स्थायी मुहावरा बन गया। 1967से1971के बीच देशभर में पांच सौ से अधिक विधायकों द्वारा दल बदलने की घटनाएँ दर्ज की गईं।राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।इसी के परिणामस्वरूप वर्ष 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची अर्थात दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। बाद में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे और कठोर बनाया गया।कानून बनने के बावजूद समस्या समाप्त नहीं हुई।नेताओं ने कानून की कमियों को समझ लिया और व्यक्तिगत दल-बदल के स्थान पर सामूहिक टूट,विलय और इस्तीफों की रणनीति अपनाई।आज स्थिति यह है कि सरकारें कई बार चुनावी जनादेश से कम और राजनीतिक प्रबंधन से अधिक बनती-बिगड़ती दिखाई देती हैं।राजनीतिक सुधारों के लिए कार्य करने वाली संस्था ए डी आर (ऐशोसिएसन फॉर डेमोक्रिऐसी रिफॉर्स)की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच देश भर में 405 विधायक दल बदलकर दोबारा चुनाव मैदान में उतरे।इनमें से 182 विधायक अर्थात लगभग 45 प्रतिशत एक ही दल में शामिल हुए।इसी अवधि में170विधायक कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में चले गए जबकि केवल 18 विधायक भाजपा छोड़कर अन्य दलों में गए। एडीआर ने यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश,गोवा,मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकारों के गिरने के पीछे विधायकों का दल-बदल प्रमुख कारण रहा।महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में दल-बदल की सबसे बड़ी प्रयोग शाला बनकर सामने आया।वर्ष 2022में शिवसेना के 55 में से लगभग 40 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गए।इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी टूट हुई और अजित पवार गुट अलग हो गया।जनता ने जिस महाविकास आघाड़ी या जिस राजनीतिक संरचना को वोट दिया था,कुछ ही वर्षों में उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया।राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि महाराष्ट्र ने भारतीय राजनीति में ₹विधायक आधारित सत्ता परिवर्तन₹ का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।इससे यह प्रश्न और प्रबल हुआ कि लोकतंत्र में वास्तविक महत्व मतदाता के वोट का है या निर्वाचित प्रतिनिधियों की बाद की राजनीतिक निष्ठाओं का।मध्य प्रदेश का उदाहरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद 22कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।परिणामस्वरूप कमलनाथ सरकार गिर गई और राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया।बाद में इनमें से अधिकांश नेता दूसरे दल के टिकट पर पुनः चुनाव लड़े।यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में दल-बदल और सत्ता परिवर्तन के सबसे चर्चित उदाहरणों में गिना जाता है।कर्नाटक में वर्ष 2019 में 17विधायकों के इस्तीफे ने एच.डी. कुमारस्वामी सरकार को गिरा दिया।कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया और नई सरकार का गठन हुआ।राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भी दल-बदल कानून की सीमाओं का उदाहरण बताया।गोवा,मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए।कई बार विपक्ष सत्ता पक्ष में बदल गया और कई बार सत्तारूढ़ दल विपक्ष में पहुँच गया।इससे लोकतांत्रिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा।एडीआर की रिपोर्ट ने भी इन राज्यों में सरकार परिवर्तन के पीछे दल-बदल को प्रमुख कारण बताया है।पश्चिम बंगाल में भी दल-बदल की राजनीति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।वर्ष 2021 के विधान सभा चुनाव से पहले और बाद में तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा के बीच नेताओं और विधायकों का आना-जाना जारी रहा।राजनीतिक गलियारों में समय-समय पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी और संभावित टूट की चचाएँ भी उठती रही हैं।लोकतंत्र के लिए केवल दल-बदल ही समस्या नहीं है,बल्कि लगातार बनी रहने वाली राजनीतिक अनिश्चितता भी चिंता का विषय है।

विश्व वर्षावन दिवस : महत्व, उद्देश्य, थीम और संरक्षण के उपाय

सुनील कुमार महला

वर्षावनों के संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस (वर्ल्ड रेन फोरेस्ट डे) मनाया जाता है। वास्तव में, यह दिवस पृथ्वी के उन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानव जीवन, जैव-विविधता और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज लॉगिंग (पेड़ों की कटाई), अवैध खनन, अनियंत्रित विकास तथा कृषि विस्तार के कारण हर मिनट लगभग 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर वर्षावन नष्ट हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 50 वर्षों में अकेले अमेजन वर्षावन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो चुका है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो पाठकों को बताता चलूं कि विश्व वर्षावन दिवस की शुरूआत वर्ष 2017 में गैर-लाभकारी संस्था रेनफोरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षावनों के संरक्षण के लिए विश्वभर के लोगों, संगठनों और सरकारों को एक साझा मंच पर लाना था। तब से यह दिवस विश्व के अनेक देशों में पर्यावरण संरक्षण अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मनाया जा रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्षावन पृथ्वी के सबसे समृद्ध और जैव-विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र हैं। यद्यपि वे पृथ्वी की भूमि का अपेक्षाकृत छोटा भाग घेरते हैं, फिर भी इनमें विश्व की लगभग आधी से अधिक वनस्पति एवं जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा पृथ्वी के जल-चक्र और वर्षा प्रणाली को संतुलित बनाए रखते हैं। लाखों आदिवासी और स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका, संस्कृति और जीवन-निर्वाह के लिए वर्षावनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली 25 प्रतिशत से अधिक दवाओं के तत्व वर्षावनों के पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनमें अनेक कैंसर-रोधी औषधियाँ भी शामिल हैं।

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को वर्षावनों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। यह सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का संदेश देता है। पिछले वर्ष अर्थात 2025 में विश्व वर्षावन दिवस की थीम एमपावरिंग एक्शन (कार्रवाई को सशक्त बनाना) रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षावनों के संरक्षण हेतु जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने पर बल देना था। इस थीम के अंतर्गत स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया था। वहीं वर्ष 2026 की थीम द फोरेस्ट विद इन यू (आपके भीतर का जंगल) है। यह थीम इस विचार को प्रस्तुत करती है कि वर्षावन भले ही भौगोलिक रूप से हमसे दूर हों, लेकिन हवा, पानी और जलवायु के माध्यम से वे हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं। यह मनुष्य और प्रकृति के गहरे एवं आंतरिक संबंध को रेखांकित करती है।

वर्षावनों से जुड़े अनेक तथ्य अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण हैं। वर्षावन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 3 प्रतिशत से भी कम हिस्से में फैले हैं, लेकिन वे विश्व की आधे से अधिक वनस्पति एवं जीव प्रजातियों का घर हैं। अमेजन जैसे विशाल वर्षावन हमारी सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा स्वच्छ जल प्रणाली से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज वर्षावनों के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन, कृषि भूमि का विस्तार, अनियंत्रित औद्योगिक एवं शहरी विकास तथा जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल के बागानों के लिए बड़े पैमाने पर वर्षावनों की कटाई की जा रही है, जो वैश्विक चिंता का विषय है। इसी प्रकार मवेशी पालन और चरागाहों के विस्तार के लिए भी बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र नष्ट किया जा रहा है।

वर्षावनों के संरक्षण के लिए हमें जिम्मेदार उपभोग की आदत विकसित करनी होगी। कागज और लकड़ी के उत्पादों का सीमित एवं समझदारीपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए। पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) को बढ़ावा देना आवश्यक है। कागज का दोनों तरफ उपयोग करना चाहिए, री-सायकल किए गए कागज और अन्य उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा जहाँ संभव हो डिजिटल विकल्प अपनाने चाहिए।इसके साथ ही सतत (सस्टेनेबल) खरीदारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। सस्टेनेबल शॉपिंग का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले यह विचार किया जाए कि वह कहाँ से आई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है तथा उसके उपयोग के बाद पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के थैले अपनाने चाहिए, ऑर्गेनिक तथा रीसायकल सामग्री से बने उत्पाद खरीदने चाहिए और स्थानीय तथा प्रमाणित उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो कम लेकिन टिकाऊ खरीदारी करनी चाहिए। पाम ऑयल से जुड़े उत्पादों के प्रति भी जागरूक रहना आवश्यक है। ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें पर्यावरण-अनुकूल और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त पाम ऑयल का उपयोग किया गया हो। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर मांस की खपत कम करने से चरागाहों के विस्तार की आवश्यकता घटेगी और वनों पर दबाव कम होगा। आदिवासी एवं स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरागत समझ रखते हैं, इसलिए उनके अधिकारों और ज्ञान की रक्षा भी आवश्यक है। साथ ही ऐसी सरकारों और कंपनियों का समर्थन किया जाना चाहिए जो सख्त पर्यावरणीय कानूनों और शून्य-वनकटाई (जीरो-डीफोरेस्टेशन) नीतियों का पालन करती हैं।

अंत में यही कहूंगा कि वर्षावनों के संरक्षण के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, झूमिंग कृषि प्रणाली को हतोत्साहित करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना आवश्यक है। वन्यजीवों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विस्तार, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों को वर्षावनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में शिक्षित करने तथा व्यापक जन-जागरूकता फैलाने की है।

वास्तव में सच तो यह है कि वर्षावनों को बचाना किसी एक देश या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज का सामूहिक और नैतिक दायित्व है। वर्षावन हमारे दैनिक जीवन, संस्कृति, स्वास्थ्य, जलवायु और भविष्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वे हमें स्वच्छ वायु, संतुलित जलवायु, जैव-विविधता और जीवनदायी संसाधन प्रदान करते हैं। यदि हम आज इनके संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण, समृद्ध जैव-विविधता और सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकेंगे। इसलिए वर्षावनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त भी है।

पारंपरिक विकल्पों में सदाबहार करियर है राजनीति विज्ञान

पारंपरिक करियर विकल्पों में राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का महत्व सदाबहार कहा जा सकता है। यह विषय समाज शास्त्र का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रशासन की विभिन्न प्रणालियों और दुनिया भर में मौजूद राजनैतिक तंत्रों व उनकी नीतियों को पढ़ाया जाता है। इसमें अध्यापन-कार्य से लेकर शोध, चुनाव व कानून से जुड़े कार्यक्षेत्रों में काम किया जा सकता है। इस समय राजनीति विज्ञान के जानकार युवाओं की पॉलिटिकल व इंटेलिजेंस एनालिस्ट या कंसल्टेंट्स के तौर पर सेवाएं ली जा रही हैं।

देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर इस विषय पर आधारित कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसलिए यह कहना कुछ हद तक सही है कि अन्य कोर्सेज की तुलना में इसमें दाखिला पाने के लिए ज्यादा मारामारी की स्थिति नहीं है। हालांकि, बेहतर मुकाम पाने के लिए इस विषय में उच्च अध्ययन की ओर रुख करना काफी महत्व रखता है। दूसरे पारंपरिक कोर्सेज की तुलना में करियर को संवारने के कहीं ज्यादा अवसर इस विषय की पढ़ाई के जरिये हासिल किए जा सकते हैं। अकादमिक और शोध कार्यों में दिलचस्पी दिखाने वाले छात्रों को देशी-विदेशी संस्थानों की स्कॉलरशिप हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके जरिए उन्हें आगे चलकर अध्यापन के बेहतर अवसर मिलेंगे।

स्कूल और कॉलेज में अध्यापन और शोध कार्यसहित अन्य क्षेत्रों में मौके होने के साथ ही हाल के वर्षों में कुछ नए करियर विकल्प भी उभरे हैं। इनमें से कुछ हैं-

पॉलिटिकल एनालिस्ट - राजनीति विज्ञान में पारंगत अनुभवी विशेषज्ञों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण करियर कहा जा सकता है। इनका काम मुख्य रूप से राजनैतिक निर्णयों/सरकारी नीतियों आदि पर समीक्षात्मक टिप्पणी करना और उनकी कमियों को उजागर करना है। ये बतौर विशेषज्ञ, पॉलिटिकल पार्टियों की नीतियों और चुनावी घोषणाओं पर भी अपने विचार देते हैं।

सोशल मीडिया मैनेजर - आम जनता के बीच जनमत तैयार करने या किसी खास राजनैतिक दल के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम देने में इस विषय की पृष्ठभूमि वाले लोगों को काफी उपयोगी माना जाता है। यही कारणहै कि सोशल मीडिया से जुड़ी नौकरी पाने में राजनीति शास्त्र के जानकार को ज्यादा परेशानी नहीं होती है।

पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स - इनका काम चुनावी दंगल में प्रत्याशियों के लिए अधिकाधिक मत पाने की योजना तैयार करना और उन्हें सफलता के साथ लागू करना होता है। यह समझ जनता के साथ लंबे समय से संपर्क में रहने के बाद विकसित होती है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का अच्छा जानकार होना इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

इंटेलिजेंस एनालिस्ट- राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों की विचारधारा को समझते हुए उनके बारे में रिपोर्ट बनाना, इनके कार्य के दायरे में आता है। ऐसे विशेषज्ञ प्राय- अप्रत्यक्ष तौर पर काम करते हैं।

मार्केट सर्वे एक्सपर्ट- बड़ी-बड़ी कंपनियां भी अपना नया उत्पाद बाजार में उतारने से पहले ऐसे विशेषज्ञों का सहारा लेती हैं, ताकि उन्हें समय-समय पर प्रतिक्रियाएं मिलती रहें। इस प्रकार वे अपने उत्पाद की त्रुटियों को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उनमें समय रहते सुधार कर दोबारा मार्केट में उतार सकते हैं।

वकील के तौर पर करियर- राजनीति शास्त्रकी पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए एलएलबी करना सही रहता है। इनके लिए मुकदमों की बारीकियों को समझना आसान होता है। वहीं जनसंचार के क्षेत्र में ऐसे सफल पत्रकारों की कमी नहीं है, जिनके पास राजनीति विज्ञान की डिग्री है। ऐसे अवसर प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में मिल सकते हैं।

पाठ्यक्रम

यह बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति विज्ञान कोई नया विषय नहीं है। इससे जुड़े कोर्सेज भी पुराने या परंपरागत कहे जा सकते हैं। दसवीं के बाद ही प्राय- एक स्वतंत्र विषय के रूप में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो जाती है। ग्रेजुएशन स्तर पर बीए/बीए (ऑनर्स) कोर्स का प्रमुख तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। आमतौर पर इन तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर ही नामी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।

व्यक्तित्व में क्या हो खास

इस क्षेत्र में ऐसे युवाओं को करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जिनको देश-विदेश में चल रही राजनैतिक उथल-पुथल और सामयिक मामलों के बारे में जानने की गहरी दिलचस्पी हो। देश के बदलते राजनैतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर और इसके सामाजिक एवं आर्थिक कारणों को समझने की दृष्टि और उनके आधार पर भावी राजनैतिक आहटों को समझने की क्षमता भी इस क्रम में एक विशिष्ट गुण कहा जा सकता है। इसके अलावा तथ्यों और तर्कों के आधार पर नीतिगत निर्णयों को समझने की काबिलियत को भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र के पेशेवरों में संवाद कौशल, भाषा पर नियंत्रण आदि का होना भी काफी मायने रखता है।

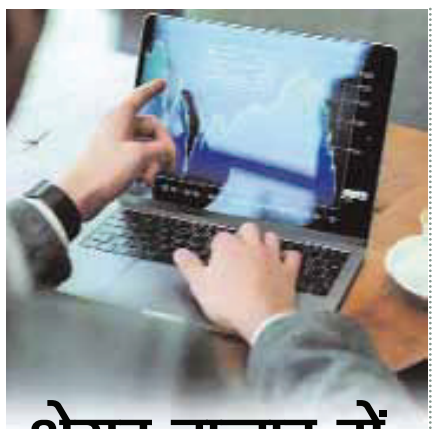

शेयर बाजार में करियर उतना ही फायदेमंद है, जितना अन्य दूसरे फील्ड

यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इन बातों को सुनकर अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो हम आपको बता दें कि आपको आधा-अधूरा सत्य बताया गया है। आम तौर पर लोग अपनी गलतियों को नहीं गिनाते। यहां पर लोगों के पैसा डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक लालच, जानकारी का अभाव, जल्दबाजी, रिसर्च का अभाव, रिस्क मैनेजमेंट न करना आदि होता है। शेयर बाजार में करियर उतना ही फायदेमंद है, जितना अन्य दूसरे फील्ड।

स्टॉक मार्केट बिजनेस नहीं, जुआ है

स्टॉक मार्केट की प्रतिष्ठा को जुए, सट्टे और अटकलों का बाजार कहा जाता है। इस तरह की गलत सूचनाओं को उन लोगों द्वारा फैलाया जाता है, जो रातो-रात अपने पैसे को चौगुना करने के प्रयास में अपने हाथ जला चुके हैं। यहां भी किसी अन्य व्यवसाय की तरह, आपके मन में उचित जोखिम-वापसी की अपेक्षा होनी चाहिए। धन सृजन एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। इसलिए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि, वे अपनी बचत को अच्छी कंपनियों में बुद्धिमानी से लगाएं और गर्वित शेयरधारक बनें। स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों के लिए केवल एक जुआ है जो रातों-रात पैसा कमाना चाहते हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए दांव लगाते हैं।

स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क

इस मार्केट में कमाई का पूरा खेल इक्विटी होल्डिंग में शामिल जोखिम और रिटर्न पर निर्भर करता है। शेयरों की कीमतों में हर दिन और कभी-कभी हर घंटे उतार-चढ़ाव आता है। हालांकि, अगर हम कुछ वर्षों का रिटर्न देखें तो कुल मिलाकर रिटर्न एक महीने या एक साल की अवधि में प्रदर्शित आंकड़ों से कहीं अधिक होगा। यह आपके लिए धैर्य यहां सफलता की कुंजी है।

स्टॉक मार्केट करियर एक स्थिर पेशा नहीं

प्रतिमाह निश्चित सैलरी पाने वाले लोग स्टॉक मार्केट को एक्स्ट्रा आय स्रोत के रूप में देखते हैं। लोग अपने जीवन में नियमित और निश्चित सैलरी चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वे हर दिन अपने करियर को नई दिशा देते हैं।

स्टॉक मार्केट करियर केवल विशेषज्ञों के लिए

किसी भी स्किल में महारत हासिल करने में समय लगता है और ऐसा ही स्टॉक मार्केट के साथ भी है। वर्तमान समय में, पर्सनल इनवेस्टर्स स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े भागीदार हैं। वित्त वर्ष 2025 में डीमैट खातों की कुल संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। खुदरा निवेशक इक्विटी कैश मार्केट में कुल वॉल्यूम का 45 फीसदी योगदान करते हैं, जो 2016 में 33 फीसदी था। यह आंकड़े एक और मिथक को खारिज करते हैं।

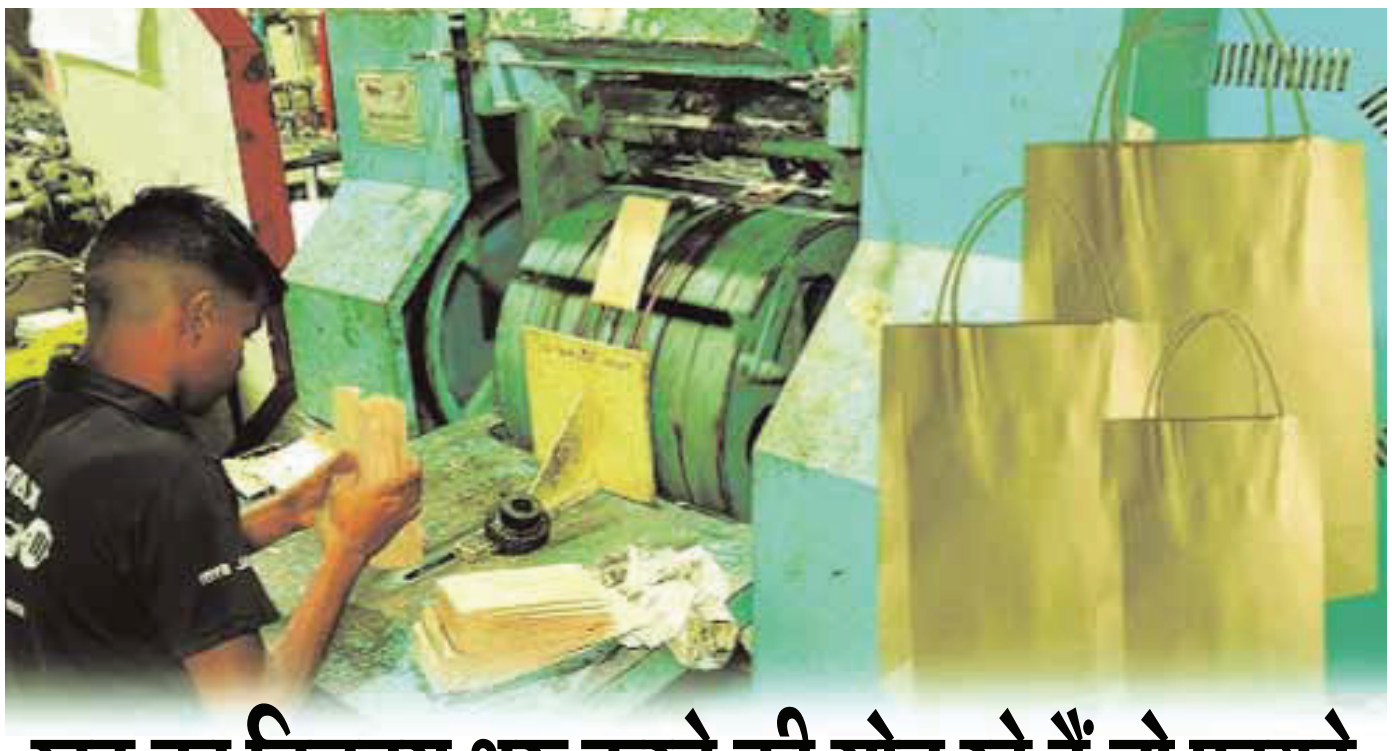

खुद का बिज़नस शुरू करने की सोच रहे हैं तो फ़ायदे वाला साबित हो सकता है पेपर बैग का आईडिया

जब से भारत सरकार ने प्लास्टिक और पॉलिथीन की बनी थैलियों पर पाबन्दी की घोषणा की है तभी से कई सारे राज्यों में इसके इस्तेमाल पर काफी हद तक बैन लग चूका है। प्लास्टिक से बनी थैलियाँ इस कदर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है की उन्हें पूरी तरह बंद करना काफी मुश्किल काम है और ये तभी संभव हो पायेगा जब इन पॉलिथीन की थैलियों का कोई विकल्प हमारे सामने होगा। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है पेपर बैग।

पेपर बैग का चलन हमारे देश में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब दुकानों, शॉपिंग मॉल व हर जगह आपको सिर्फ पेपर बैग ही दिखाई देंगे। इस समय मार्केट में पेपर बैग की मांग बहुत ज्यादा है तो ऐसे में अगर आप खुद का बिज़नस शुरू करने की सोच रहे है तो ये आईडिया आपके लिए बहुत ज्यादा फ़ायदे वाला साबित हो सकता है क्योंकि इस बिज़नस में कम्पीटीशन बहुत कम है और अगर आपने सही दिशा में जी तोड़ मेहनत कर ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।

व्यापार का अवसर एवं क्षेत्र

प्लास्टिक थैलियों के मुकाबले पेपर बैग दिखने में काफी स्टाइलिश होते है। और बड़े शहरों में लोगो के बीच इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। निम्न जगहों पर पेपर बैग बहुत ज्यादा प्रचलित हैं - किराने की दुकानों पर, शॉपिंग मॉल में, मेडिकल स्टोर्स पर, फ़ल व सब्जियों की दुकानों पर पेपर बैग की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है की आने वाले कुछ सालों में पेपर बैग मेकिंग बिज़नस अरबों रुपयों का हो जायेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है की ये इको-फ्रेंडली होने के साथ-साथ बहुत सस्ते भी है। पेपर बैग को आसानी से रीसाइकिल किया जा सकता है और वातावरण को इससे ज़रा भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए जितनी जल्दी आप यह बिज़नस स्टार्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा।

व्यापार के लिए जगह का चुनाव

किसी भी व्यापार के लिए सही जगह का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिज़नस शुरू करने से पहले कुछ बातों की पूरी जानकारी लेना बहुत जरुरी है क्योंकि अगर एक बार मशीनें इनस्टॉल हो गई तो उन्हें वापस से दूसरी जगह इनस्टॉल करना बहुत भरी पड़ सकता है। इसके लिए आप निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखें

- पेपर बैग मेकिंग बिज़नस के लिए जगह ऐसी लोकेशन पर हो कि आसपास के लोगों को मशीनों की आवाज़ से कोई परेशानी न हो। इसके लिए आप शहर कुछ दूरी पर जगह का चुनाव करें ध्यान रहे उस जगह की शहर से ज्यादा दूरी न हो।
- उस जगह से शहर तक सड़क की अच्छी व्यवस्था हो।
- माल लाने व ले जाने के लिए गाडियों के पहुचने की व्यवस्था हो।
- पानी व बिजली की व्यवस्था हो।
- मजदूर आसानी से उपलब्ध हो।

व्यापार पंजीकरण

पेपर बैग व्यापार शुरू करने से पहले अपने बिज़नस को रजिस्टर करवाना बिलकुल भी न भूले। इसके लिए आपको अपने कस्बे या शहर की नगर-पालिका/नगर-निगम से ट्रेड लाइसेंस व साथ ही भारत सरकार की और से ज़ारी की जाने वाली उद्योग आधार संख्या के लिए आवेदन करना होगा।

मशीनों की जानकारी

पेपर बैग बनाने के लिए मार्केट में कई सारी अलग अलग कंपनियों की मशीने उपलब्ध है। जिनमे से कुछ स्वचालित है तो कुछ को आपको खुद को ही चलाना होगा। ऐसी भी बहुत सारी मशीनें है जो पेपर बैग बनाने के साथ साथ उन पर प्रिंटिंग की सुविधा भी देती है। इन्ही सब खूबियों की वजह से इनकी कीमतों में अंतर है। पेपर बैग बनाने की मशीन की कीमत 3 लाख रूपए से लेकर 20 लाख रूपए तक हो सकती है। जितनी महँगी मशीन होगी पेपर बैग का उत्पादन व गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। मशीन को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते है।

आवश्यक कच्चा माल

पेपर बैग बनाने के लिए कई तरह के कागजों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कागज़ अच्छी क्वालिटी वाले तो कुछ बहुत ही हल्के होते है। अगर आप शोपिंग मॉल को ध्यान में रखते हुए पेपर बैग बना रहे है जहाँ ग्राहकों द्वारा एक साथ कई सारे सामान, कपड़े और ग्रोसरी खरीदी जाती है तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाला कागज़ ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप सस्ता विकल्प ढूंड रहे है तो कागज़ के लिए अख़बार का इस्तेमाल भी कर सकते है लेकिन यह आपके ब्रांड की वैल्यू मार्केट में कम कर देगा। यह आपको निश्चय करना है की आप कौनसा कागज़ इस्तेमाल में लेते हो। पेपर बैग बनाने के लिए ये चार चीज़े अत्यधिक आवश्यक है- पेपर रोल, चिपकाने के लिए गौद, छपाई के लिए प्रिंटिंग इंक, बैग स्ट्रिप।

पेपर बैग बनाने की प्रक्रिया

पेपर बैग बनाने का काम पूर्णतया मशीन द्वारा ही किया जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो मशीन चलाना जानता हो आसानी से उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। आपको केवल एक बार जरुरी पेपर रोल, गौद, छपाई के लिए प्रिंटिंग इंक मशीन में लगानी है उसके बाद मशीन स्वत- ही अपना काम करने लगती है।

कुल लागत का गणित

अगर आप छोटे स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते है तो आपको मशीन के लिए कम से कम 3 से 5 लाख खर्च करने पड़ेगें। मशीन के आलावा भी अन्य कच्चा मॉल, जगह का किराया, बिजली का बिल, मज़दूर की तनख्वाह, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिलाकर इसकी कुल लागत 6 से 7 लाख रूपए तक पड़ेगी।

मार्केटिंग एंड प्रमोशन

अपने बिज़नस की मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका अपना सकते है। ऑफलाइन मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए आप अपने शहर के साथ-साथ नजदीकी शहरों या कस्बों में शोपिंग मॉल, किराने की दुकानों, फ़ल व सब्ज़ियों की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स आदि पर जा कर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते है। इसके लिए आपको विजिटिंग कार्ड और पम्पलेट जिसमें अपने प्रोडक्ट की सारी खूबियाँ व मूल्य व्यवस्थित रूप से निर्धारित किये गए हो की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन मार्केटिंग करने से पहले आपको खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। उन सवालों के जवाब आपको पहले से ही तैयार रखने होंगे जो आपके कस्टमर्स आप से पूछ सकते है।

कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन मार्केटिंग करने से पहले एक अच्छे इंस्टिट्यूट से मार्केटिंग की जरुरी स्किल जरुर सीख लें। और अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो मार्केटिंग के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति को नौकरी पर भी रख सकते है। ऑनलाइन मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए कई सारे तरीके उपलब्ध है।

वर्तमान में लोगों के बीच इन्टरनेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे अच्छा फायदा यह है की इन्टरनेट की मदद से घर बैठे आप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो और इसमें होने वाला खर्चा भी ना के बराबर है। तो बिलकुल भी देर मत कीजिये और पेपर बैग किंग बनने की दिशा में अपना पहला कदम जल्दी से जल्दी बढाइये।

पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में नौकरियां पा सकते हैं कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट

कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना हर युवा का सपना होता है। वहीं, यदि आप अभी भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के बाद क्या करें, तो यहां कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद कुछ बेहतरीन करियर हैं। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट्स के लिए कई करियर ऑप्शन हैं और इससे करियर ग्रोथ भी ज्यादा होती है। कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में नौकरियां पा सकते हैं।

सॉफ्टवेयर डेवलपर

एक फुल-स्टैक सॉफ़्टवेयर डेवलपर सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम बनाने के बेसिक काम में शामिल होता है। वे ऐसे एप्लिकेशन या प्रोग्राम बनाते हैं जो कंपैटिबल होते हैं ताकि सॉफ़्टवेयर को किसी भी डिवाइस पर देखा और आसानी से संभाला जा सके और देखने के लिए बहुत पोर्टेबल हो।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

C, C++, C#, Java, Python और कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनकी सही कमांड की आवश्यकता होती है। इसलिए यह करियर बी-टेक छात्र के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद सबसे अच्छे करियर में से एक माना जाता है। एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी की प्रगति के बावजूद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग और आवश्यकता वर्ष 2050 तक भी बरकरार रहेगी।

डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर

एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदा सॉफ़्टवेयर मॉडिफिकेशन की जाँच करता है। यह एक आवश्यक जिम्मेदारी है क्योंकि इसमें बहुत सतर्क रहना और कंपनी डेटाबेस और उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना शामिल है। बैंकिंग, बीमा और सर्विस कंपनियों जैसे संगठन, एलिजिबल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छी जॉब देते हैं।

कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर

कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स जैसे राउटर, सर्किट बोर्ड और मेमोरी डिवाइस का विकास, डिजाइन और परीक्षण करता है। इस काम के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज और क्रिएटिविटी के बीच अच्छे सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना उनका काम है कि हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है।

सिस्टम एनालिस्ट

कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, इनफॉरमेशन सिस्टम के प्रत्येक संगठन का डीप एनालिसिस करने और उचित सुधार का सुझाव देने के लिए मौजूद होता है। बढ़ते आईटी बिज़नेस के साथ, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की मांग भी बढ़ रही है। फाइनेंस कंपनियों, सरकार, बीमा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के कई अवसर हैं।

कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट

कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट के साथ नेटवर्किंग और कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डिजाइन, स्थापित और प्रबंधित करता है। काम डेटा प्रोसेसिंग और सहयोग के संदर्भ में संगठनों की इच्छाओं को पहचानना है।

वेब डेवलपर

वेब डेवलपर्स के पास पेज लेआउट, वेबसाइट स्टाइलिंग और पेज फीचर्स की मदद से किसी विशेष वेबसाइट पर विज़िटर के अनुभव को ढालने का एक आकर्षक काम है। एक वेब डेवलपर को HTML, CSS, JavaScript जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उचित समझ होनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि एक सर्वर विभिन्न डिवाइस के साथ कैसे काम करता है। पूरी दुनिया में वेब डेवलपर्स की भारी मांग है। अगले दस वर्षों में इसके 13त्न बढ़ने का अनुमान है।

प्रोजेक्ट मैनेजर

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद यह सबसे अच्छे करियर में से एक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्रोग्रामिंग टीम के प्रयासों को एक साथ लाना है और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके काम का समर्थन करना है। एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य तक, लगभग हर उद्योग को प्रोजेक्ट मैनेजर की आवश्यकता है। इसलिए इस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान विषय पर बैठक: जिला आधारित विकास मॉडल विकसित राजस्थान का आधार

विकसित भारत के संकल्प में अग्रणी भूमिका निभा रहा राजस्थान- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम आ रहे नजर

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं को केंद्र में रखकर विकास की नई अवधारणा विकसित की जा रही है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।

प्रो. के.वी. राजू ने की राज्य सरकार की सराहना-

प्रो. के.वी. राजू ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान अचीवर्स श्रेणी का प्रदेश है और यहां पेयजल, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं में अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन, कृषि, खनन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं है। उच्च तकनीक आधारित डेटाबेस तैयार कर इन क्षेत्रों को जीएसडीपी में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग के साथ क्षमता संवर्धन करने एवं असंगठित क्षेत्र में सर्वे हेतु सैंपल साइज बढ़ाने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के. वी. राजू की उपस्थिति में जिला घरेलू उत्पाद अनुमान विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग, निवेश और सुशासन आधारित नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है। प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित हो रहा है तथा वर्तमान में 6 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स युवाओं को रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

संतुलित एवं नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों से लेकर गांव और वार्ड स्तर तक संतुलित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत आमजन के सुझावों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 2030, 2035 और 2047 को ध्यान में रखते हुए विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ा,स्थानीय उत्पाद को मिल रही पहचान

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इससे चूरू के हस्तशिल्प उद्योग, भरतपुर के सरसों आधारित छोटे उद्यम तथा बांसवाड़ा एवं उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित पारंपरिक जनजातीय उत्पादों जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, उनकी आर्थिक गतिविधियों का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी परिलक्षित हो रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में पंच गौरव के अंतर्गत जिला आधारित उपज, उत्पाद, वनस्पति, खेल व पर्यटन में नवाचार किए जा रहे हैं।

आकांक्षी उपखण्डों से वोकल फॉर लोकल विजन हो रहा साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन को साकार करते हुए प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विशेषताओं, स्थानीय आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के आधार पर आकांक्षी उपखण्डों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख फसल, उत्पाद एवं उत्पादन को चिन्हित कर प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन की प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी उपखण्डों को प्रोत्साहित कर लघु, कुटीर एवं पारंपरिक उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान किया जा रहा है, जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ जिला सकल उत्पाद प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में सरकार कृषि, पशुधन, डेयरी, सहकारिता, खनन तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में डेटा आधारित विकास मॉडल विकसित कर रही है। जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी और मूल्यांकन के लिए डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह पोर्टल विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक संकलन और विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज देश के अग्रणी अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश और नवाचार राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ सतत विकास के लक्ष्य को भी मजबूत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला आधारित विकास, डेटा आधारित नीति निर्माण, स्थानीय उद्यमों के सशक्तीकरण, नवाचार, निवेश संवर्धन तथा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बल पर राजस्थान विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बैठक में राजस्थान के प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने संबंधी एवं राज्य के आर्थिक परिदृश्य तथा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे एवं सभी संभागीय आयुक्त तथा कलक्टर्स वी.सी के माध्यम से जुड़े।

एसआई भर्ती-2021 में लीक पेपर पढ़कर पास हुआ अभ्यर्थी गिरफ्तार:लिखित परीक्षा में हासिल किए थे अच्छे नंबर, इंटरव्यू में फेल हुआ

जयपुर

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस SOG विशाल बंसल ने बताया- RPSC के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा लीक किए गए पेपर को पढ़कर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मनीष दाधीच को गिरफ्तार किया गया है।

मनीष दाधीच ने अपने भाई पुरुषोत्तम दाधीच और संदीप कुमार लाटा के जरिए लीक पेपर हासिल किया था। आरोप है कि बाबूलाल कटारा द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्नपत्र और उत्तर परीक्षा से पहले पढ़कर उसने लिखित परीक्षा दी। इसके परिणामस्वरूप मनीष ने हिंदी सब्जेक्ट में 200 में से 170.08 अंक और सामान्य ज्ञान में 200 में से 158.69 अंक प्राप्त किए थे। इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित अंक नहीं मिलने के कारण उसका अंतिम चयन नहीं हो सका।

भाई पहले हो चुका गिरफ्तार

SOG ने इससे पहले 2 जून 2025 को पुरुषोत्तम दाधीच और 4 जून 2025 को संदीप कुमार लाटा को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि दोनों आरोपियों ने लीक पेपर प्राप्त कर अपने परिचित अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पढ़वाकर लिखित परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाया। दोनों के खिलाफ 31 जुलाई 2025 को कोर्ट में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। वर्तमान में दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। अपने-अपने विभागों में निलंबित चल रहे हैं। SOG के अनुसार, मनीष दाधीच गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक स्तर ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आखिरकार उसे 19 जून को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 23 जून 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

गहलोत बोले-पार्टी जिसको मजबूत समझे, उसको आगे लाए

मैं सबसे संतुष्ट नेता; प्रसूताओं के इलाज में सरकार फेल, हार के डर से नहीं करा रही चुनाव

जालोर

पूर्व सीएम अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को जालोर पहुंचे। उन्होंने कहा- वर्तमान सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और धरना-प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।

सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार की सुनने की क्षमता समाप्त हो गई। बालोतरा रिफाइनरी में हाल ही में हुई चूक के कारण ही पीएम का दौरा भी रद्द करना पड़ा। यह बड़ी लापरवाही है, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि दिल्ली जाने या राजस्थान में रहने के सवाल पर गहलोत ने मारवाड़ी अंदाज में कहा कि 'मैं थासू दूर नहीं' (मैं आपसे दूर नहीं हूं)। राजस्थान की जनता और आलाकमान ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री और कई बार सांसद-विधायक बनाकर सब कुछ दिया है। वह खुद को देश का सबसे संतुष्ट राजनेता मानते हैं और पार्टी उन्हें संगठन, दिल्ली, जोधपुर या जालोर में जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे वे बिना किसी मांग के स्वीकार करेंगे। पार्टी जिसको मजबूत समझे, उसको आगे लाए।

दरअसल, गहलोत जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर के निवास स्थान पर पहुंचे थे, जहां उनके दिवंगत पिता की शोक सभा में शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संजय नगर स्थित कांग्रेस के नए कार्यालय भवन का निरीक्षण भी किया।

प्रसूताओं के इलाज में सरकार फेल

कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के सरकारी अस्पताल में एक साथ 8 प्रसूताओं को इंफेक्शन होने की घटना पर गहलोत ने पीड़ित परिवारों को सरकार से मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों से मिलकर आया हूं। इस मामले में सरकार फेल हो चुकी हैं।

अपनी पुरानी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त की थीं, जो पूरी दुनिया में बेमिसाल हैं, यहां तक कि अमेरिका में बराक ओबामा की ऐसी ही योजना फेल हो गई थी, लेकिन हमारी योजना बेहद कामयाब रही।

भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर हुंकार रैली, सांसद बोले- राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा

भरतपुर

भरतपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ बोलने से नाराज नदबई विधायक जगत सिंह मंच छोड़कर चले गए। बेनीवाल को रोकने के लिए विधायक खड़े हुए और उसने हाथ मिलाया। इसके बाद भी बेनीवाल नहीं माने तो जगत सिंह ने गर्दन हिलाकर मना किया और मंच से उतरकर चले गए। बेनीवाल ने कहा- आज की रैली के बाद यह तय है कि राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा।

नागौर सांसद सोमवार को भरतपुर के नुमाइश मैदान में हुई आरक्षण रैली को संबोधित कर रहे थे। इसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी जाट समाज के लोग शामिल हुए।

रैली भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर की गई थी। इससे पहले डीग में रैली में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ लोग पुलिस से उलझ गए थे। उनका आरोप था कि पुलिस उन्हें जबरन रोक रही थी।

बेनीवाल बोले- मैं कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता

हनुमान बेनीवाल ने कहा- भरतपुर-धौलपुर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इस चीज की आग जाट समाज के दिल के अंदर है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता और मैं किसी से नहीं डरता। मन में जो बात होती है वो कह देता हूं। भरतपुर के जाट स्वाभिमानी है।

डीजे बंद करने के लिए कहा तो कहासुनी हो गई थी

आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि- रैली के बारे में जानकारी और लोगों को बुलाने के लिए पीले चावल बांटे गए थे। वहीं, डीग में लोगों की पुलिस से हुई बहसबाजी को लेकर अधिकारियों का कहना है लोग डीजे बजाते हुए आ रहे थे। इन्हें डीजे बंद करने के लिए कहा तो कहासुनी हो गई थी।

सीएस ने पीएम एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा की

नीति आयोग की 11वीं शासी बैठक में राज्य में शिक्षा लिए गये निर्णयों को आगे बढ़ाने के निर्देश

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर मुख्य सचिव ने दी बधाई, 11 विद्यालयों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

जयपुर।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित पीएम श्री एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) की एक समीक्षा बैठक में राज्य में शिक्षा विभाग के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त पर एसीएस, एजुकेशन श्री राजेश यादव समेत अन्य विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों और सभी स्टेकहोल्डर्स को बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के लिए देशभर में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2025 के तहत राजकीय विद्यालयों की कक्षा 3, 6 एवं कक्षा 9 में भाषायी एवं गणितीय ज्ञान में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहने पर भारत सरकार के सचिव ने सराहना की है। एनएएस में राजस्थान तीनों ग्रेड कैटेगरी (ग्रेड 3, 6 और 9) में टॉप 10 राज्यों में शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली - 2026 पर नीति आयोग की 11वीं शासी बैठक में बेसिक सुविधाओं और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन, निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में हुई प्रोग्रेस, और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कूल बोर्ड को मज़बूत करने एवं गुणवत्ता की पहल पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए अपार आईडी की 100 प्रतिशत पहुंच पूरी करने, स्टेट ओपन स्कूल्स के तहत कवरेज बढ़ाने, और टीचर्स के लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट इत्यादी निर्णय को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने बताया कि नीति आयोग की भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट - 2026 में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (एमएसआरए) को राज्य की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिस में से एक माना है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने पीएम श्री विद्यालयों से संबंधित जानकारी एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाले लीफलेट का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री विद्यालयों की अवधारणा एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था की सराहना की।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित हो - सीएस

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत संचालित एफएलएन, निपुण राजस्थान एवं प्रखर राजस्थान 2.0 के सकारात्मक परिणामों की सराहना की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से पीएम श्री विद्यालयों में बालिका शौचालयों की उपलब्धता, लर्निंग एवं क्वालिटी आउटकम्स पर जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर कम करने, स्मार्ट क्लास एवं पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में विद्या समीक्षा केंद्र (ङ्कस्र्च) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के मॉडल हैं पीएम श्री विद्यालय-

बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश यादव ने पीएम श्री एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 649 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के मॉडल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है तथा नव निर्माण एवं मरम्मत कार्य भी प्रगति पर हैं।

उन्होंने यह बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राज्य के अन्य राजकीय विद्यालयों में भी शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसकी शुरुआत 29 मार्च, 2025 को की गई थी, के अंतर्गत राज्य के 69 हजार से अधिक राजकीय विद्यालयों में विभिन्न सुधारात्मक गतिविधियां लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के परिणामस्वरूप विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ी है, ड्रॉपआउट में कमी आई है तथा परीक्षा परिणामों में भी सकारात्मक सुधार दर्ज किए गए हैं। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा डॉ. रश्मि शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट, आरएससीईआरटी निदेशक श्रीमती स्वेता फगेडिया, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा, विभागीय उपायुक्त एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)